Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide basic facilities at Passport Seva Kendra in Meerut, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद अथवा लोक सभा क्षेत्र में 'पासपोर्ट सेवा केन्द्र' खोले जाने से इन सेवाओं में बहुत बड़ा सुधार हुआ है । पूरे भारत में 419 से अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं, जो देश के कोने-कोने में लोगों को आसान और सुविधाजनक पासपोर्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं । परन्तु अध्यक्ष जी, मेरठ के पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अधिकारियों की लापरवाही के कारण मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । लगातार बिजली कटौती की खबरें आती हैं, जो कई बार 5-5 घंटे की हो जाती हैं । इस सेवा केन्द्र में पेयजल आपूर्ति से लेकर, पंखे इत्यादि की भी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है । असुविधा के कारण दूर-दराज से आए हुए आवेदकों को कई बार वापस जाने के लिए भी कह दिया जाता है । अध्यक्ष जी, इन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के संबंध में विदेश मंत्रालय तथा डाक विभाग में एम.ओ.यू. हुआ, जिसके अंतर्गत डाक परिसर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी डाक विभाग की थी तथा इन सब कार्यों के लिए डाक विभाग को प्रति फाइल 300 रुपये दिए जाते हैं । मेरठ में स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्र द्वारा डाक विभाग को इस केन्द्र में संशोधित होने वाली रोजाना की लगभग 40 फाइलों के हिसाब से प्रतिमाह लगभग 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है, परन्तु स्थानीय स्तर पर डाक विभाग के अधिकारियों को लगातार कहे जाने के बावजूद उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही का संज्ञान लेते हुए डाकघर और पासपोर्ट कार्यालयों के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित करे ताकि पासपोर्ट सेवा

केन्द्रों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें तथा आवेदकों को असुविधा का सामना न करना पड़े ।